Statement—B

Funds released (Central+State) during last five years under EAS

(Rs. in Lakhs)

SI. No.	Name of the State/UT	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1.	Andhra Pradesh	4500.00	12987.50	18187.50	25137.50	20925.00
2.	Arunachal Pradesh	300.00	1200.00	2323.75	2126.25	2362.50
3.	Assam	2587.50	5790.00	10025.00	13525.00	10740.00
4.	Bihar	5887.50	12987.50	20287.50	26556.25	22792.50
5.	Goa	0.00	0.00	0.00	100.00	175.00
6.	Gujarat	606.25	4475.00	8712.50	7312.50	5400.00
7.	Haryana	1650.00	3600.00	4150.00	3350.00	3337.50
8.	Himachal Pradesh	43.75	625.00	562.50	1987.50	3187.50
9.	J & K	1043.75	3687.50	8425.00	4825.00	5950.00
10.	Karnataka	3525.00	8187.50	13712.50	14450.00	13250.00
11.	Kerala	725.00	1700.00	2312.50	3562.50	4986.25
12.	Madhya Pradesh	7118.75	18170.00	28675.00	28337.71	26884.81
13.	Maharashtra	3306.25	9027.50	14325.00	8412.50	14168.14
14.	Manipur	825.00	1237.50	1125.00	1350.00	1012.50
15.	Meghalaya	200.00	800.00	312.50	612.50	275.00
16.	Mizoram	750.00	2000.00	1500.00	1500.00	1000.00
17.	Nagaland	1050.00	1400.00	2600.00	3482.50	2625.00
18.	Orissa	5335.00	9855.00	14325.00	20534.44	18401.98
19.	Punjab	0.00	0.00	0.00	1225.00	2300.00
20.	Rajasthan	4575.00	12375.00	17537.50	12987.50	11581.25
21.	Sikkim	145.00	200.00	412.50	275.00	275.00
22.	Tamil Nadu	1318.75	4927.50	10512.50	18406.25	23400.00
23.	Tripura	762.50	2272.50	1950.00	2700.00	1800.00
24.	Uttar Pradesh	3507.81	13737.50	19450.00	26630.94	39310.08
25.	West Bengal	5068.75	9622.50	11550.00	12712.50	9737.50
26.	A & N I.	10.00	40.00	40.00	0.00	80.00
27.	D & N H.	5.00	20.00	30.00	60.00	30.00
28.	Daman & Diu	5.00	0.00	20.00	20.00	0.00
29.	Lakshadweep	25.00	100.00	100.00	140.00	0.00
30.	Pondicherry	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
	TOTAL	54876.56	141025.00	213163.75	242379.34	246047.50

गुजरात और महाराष्ट्र में ग्रामीण विकास योजनाएं

1221.**श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात और महाराष्ट्र सरकार की उदासीनता के कारण अनेक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों/योजनाओं को स्थगित कर दिया हैं,

(ख) यदि हां, तो योजनाओं के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं,

(ग) इन योजनाओं के लिए कुल कितना वित्तीय आबंटन किया गया हैं, और वर्तमान में इन योजनाओं की वास्तविक स्थिति क्या है, और

(घ) क्या सरकार के पास इन योजनाओं को पुनः प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव विचारधीन हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील) : (क) और गुजरात और महाराष्ट्र सरकार की उदासीनता के कारण कोई महाराष्ट्र सरकार की उदासीनता के कारण कोई कार्यक्रम/योजना स्थगित नहीं किया गया हैं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Poverty alleviation schemes

1222. SHRI P. PRABHAKAR REDDY: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the number and names of various schemes for poverty alleviation in rural areas initiated by Government since they came to power in March, 1998;

(b) whether these schemes have been included in Ninth Plan and if so, the total allocations made for these schemes;

(c) the amount sanctioned for the implementation of these programmes during the current financial year; and

(d) whether the work has been initiated on any of these schemes and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABA GOU-DA PATIL): (a) No new scheme has been introduced for poverty alleviation in rural areas by the Government since March, 1998.

(b) to (d) Question does not arise. 1223.

देश की बेरोजगार कारीगर

1223. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यवार निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या हैं,

(ख) क्या सरकार बड़े पैमान पर औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए ग्रामीण कारीगरों को कोई प्रोत्साहन दे रही हैं,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं,

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत प्रशिक्षित कारीगर आज भी बेरोजगार हैं, और

(ड़) यदि हां, तो उनके पुर्नवास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण रोजगार योजनाओं अर्थात् वर्षों के दौरान ग्रामीण रोजगार योजनाओं अर्थात् जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, दस लाख कुंओं की योजना, समन्वित ग्रामीण दस लाख कुंओं की योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्व-रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण महिला तथा बाल विकास, तथा ग्रामीण कारीगरों के उन्नत औजार किटों की आपूर्ति की योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियों के राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरे अनुपत्र में दिए गए हैं ।

[**देखिये परिशिष्ट** 185, **अनुपत्र सं**0 32]

(ख) पड़े पैमाने पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए ग्रामीण रोजगार योजनाओं के अंतर्गत कुशल ग्रामीण कारीगरों को प्रोत्साहन देने का कोई प्रावधान नहीं हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(क) और (ड़) ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत रूप से प्रशिक्षित कारीगरों की रोजगार स्थिति की मॉनिटरिंग नहीं की जाती हैं ।

Construction of rural roads in Andhra Pradesh

1224. DR. MOHAN BABU: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the details of construction of rural roads in Andhra Pradesh during the Eighth Plan period;

(b) the details of rural roads proposed to be constructed during the Ninth Plan period in Andhra Pradesh;

(c) whether sufficient funds have been made available for the purpose; and

(d) if not, how do Government propose to accelerate the socio-economic development in the State?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND